



GRAVITA INDIA LTD.

Corp. Office : 402, Gravita Tower, A-27 B, Shanti Path,
Tilak Nagar, JAIPUR-302 004, Rajasthan (INDIA)
Phone : +91-141- 2623266, 2622697 FAX : +91-141-2621491
E-mail : info@gravitaindia.com Web. : www.gravitaindia.com
CIN : L29308RJ1992PLC006870

31st May, 2018

GIL/2018-19/48

To,

The BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400 001 Fax No.: 022-22722041 Scrip Code- 533282	The listing Department The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra- Kurla Complex Bandra(east) Mumbai- 400 051 Fax No.: 022-26598237/38 Company Code- GRAVITA
--	---

Sub: Submission of copy of the newspaper advertisements in respect of transfer of equity shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Suspense Account.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47(3) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose a copy of the Notice published in the newspapers [The Financial Express (English) and Nafa Nuksan (Hindi)] in connection with the proposed transfer of Equity Shares to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Suspense Account pursuant to the provisions of section 124(6) of the Companies Act, 2013 and the rules referred there under.

Kindly take the same on record.

Thanking You.

Yours Faithfully

For Gravita India Limited


Nitin Gupta
Company Secretary
ACS: 31533



Encl: As above

फितकी के अनुसार
गत वित्त वर्ष की जीडीपी
रहेगी 6.6 प्रतिशत

नयी दिल्ली। प्रमुख कारोबारी संघटना फिक्की ने अनुमान लगाया है कि गत वित्त वर्ष के दौरान देश को विकास दर 6.6 प्रतिशत रह सकती है। हालांकि फिक्की ने यह भी कहा है कि बाते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के दौरान यह दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उद्योग मंडल फिक्की ने आज यह बात कही। पूरे वित्त वर्ष 2017-18 में जीडीपी को वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़े 31 अप्रैल को जारी करने वाला है। फिक्की के आर्थिक परिदृश्य सर्वे में कहा गया है कि पूरे वित्त वर्ष 2017-18 में स्थिर मूल्य पर जीडीपी की वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बाते वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रही है। फिक्की का यह सर्वे अर्थशास्त्रियों की राय पर आधारित है। फिक्की ने कहा कि 2018-19 में जीडीपी की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह न्यूनतम 6.9 प्रतिशत और अधिकतम 7.5 प्रतिशत रह सकती है। फिक्की के सर्वे में विदेश में घटनाक्रमों पर कुछ चिंता जताई गई है। इसमें 2018-19 में औसत चालू खाते का घाटा (कैड) जीडीपी के 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे में कहा गया है कि कच्चे तेल के बढ़ते दाम समस्या बड़ा जोड़िये हैं। इसके अलावा कमजोर रुपये की वजह से आयात पर दबाव बढ़ सकता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि संसद के शेष हिस्से में भी रुपये दबाव में रह सकता है। फिक्की के अनुसार अर्थशास्त्रियों में इसको लेकर एकमत है कि व्यापार युद्ध की वजह से भारत अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है।

- पीटीआई

ई-ऑफिस व्यवस्था 15 अगस्त से पूरे उत्तर प्रदेश में होगी लागू

लखनऊ। सरकारी कामकाज में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आई—ऑफिस व्यवस्था 15 अगस्त से पूरे प्रदेश में लागू करने का प्रहरी है। राज्य सरकार के अथक प्रवक्ता ने आज बताया कि मुख्मन्त्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कल उक्त फैसला किया गया। प्रवक्ता ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों को आई—ऑफिस व्यवस्था के तहत लाया जाएगा ताकि सरकारी विभागों में कम से कम कामकाज का इस्तेमाल हो। उन्होंने बताया कि राज्य कैबिनेट ने सिद्धार्थनाथ, एटा, गाजीपुर और फतेहपुर के जिला या रेफरल अस्पतालों का उद्घाटन कर उन्हे मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने प्रमाणित बीज खरीदने पर किसानों को 50 फीसदी तक सब्सिडी देने का प्रस्ताव मंजूर किया है।

आईएनएक्स मीडिया मामले में अग्रिम जमानत के लिये उच्च न्यायालय पहुंचे चिदंबरम

नयी दिल्ली। एयरसेल मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से थोड़े वक के लिये आहत पक्षों के कुछ ही घंटे बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने आज राईपनवास मॉडिया भ्रष्टाचार मामले में अग्रिम जमानत के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय को आज दरजाया खटखटाया। चिदंबरम की तरफ से अधिवक्ता पी पी के दुबे ने याचिका दायर की है। मामले का, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशराजीव गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिश्चंकर की पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया। पीठ ने मामले को आज ही सुचीबद्ध करने की अनुमति देने दी। वकीलों ने इस याचिका मामला बाद में न्यायमूर्ति एस पी गंगा के समक्ष दिया। उन्होंने बाद पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इससे पहले दिन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने एयरसेल मैक्सिस धन शोधन मामले में विशेष न्यायाधीशराजीव ओ पी सैनी के पास अग्रिम जमानत याचिका दायर की। सैनी ने उलट हज्जेसी को और से जारी सम्पत्ति के अनुपार पांच जून को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी करके पांच जून तक उससे जवाब मांगा। साथ ही उसे निर्देश दिया कि वह तब तक मामले में चिदंबरम के खिलाफ कोई भी दबाव न डाले। वला कार्यवाई नहीं करे।

- पीटीआई

गैस व्यापार केंद्र दिसंबर से पहले परिचालन में आएगा

हरियाणा: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) को उम्मीद है कि प्रस्तावित गैस व्यापार केंद्र दिसंबर से पहले चालू हो जाएगा। एक्सचेंज के लिए नियम तय करने को सरकार और नियामक को मदद के लिए क्रिसिल को नियुक्ति की गई है। पीएनजीआरबी के सदस्य सभापालन में ने कहा, “ हमने गैस कारोबार हब की थापना में सलाह देने के लिए क्रिसिल को नियुक्ति की है। वे हमें नियमन तय करने में मदद करेंगे, उन्हें इसके लिए 11 मई से 18 सप्ताह का समय दिया गया है। क्रिसिल वैश्विक रेटिंग एवं अनुसंधान एजेंसी है। गर्ग ने यहां शहर गैस वितरण (सीजीडी) की नौवें दौर की बोली के लिए अप्रैल पेश होने के मौके पर अलग से अलग से बातचीत में कहा, “ सरकारी रोड की ओर से भी काफी चीजों की जरूरत है। सरकार और हम दोनों चाहते हैं कि गैस कारोबार हब चालू कैलेंडर सत्र के दौरान ही परिचालन में आ जाए। उन्होंने कहा कि योह मांग अप्रैल की सप्ताह की एक्सचेंज की तर्ज पर काम करेगा। इसमें कीमत हब और आपूर्ति तथा बाजार के हिसाब से तय होती है।

- पीटीआई

कुमारस्वामी ने 15 दिन में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया

बालपुर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस डी कुमारस्वामी ने आज कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता किसानों को बचाना है। उन्होंने 15 दिन के अंदर किसानों की कर्ज माफी की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने का वादा किया और इस बात पर जोर दिया कि अब वह " पीछे हटने वाले नहीं " हैं। किसान समुदाय के लिये चुनाव पूर्व आश्वासन को पूरा करने में कथित तरीका को लेकर कुमारस्वामी पर भाजपा हमलावर है। इसलिए किसानों की समस्याओं पर चर्चा के लिये उन्होंने किसान सभूत के प्रतिनिधियों और प्रागतिशील किसानों से मुलाकात की।

करीब तीन घंटे तक किसानों की बात सुनने के बाद उन्होंने बैठक में मौजूद लोगों को संशोधित करके हुए कहा, “ 15 दिन में इस लोग एक फैसले पर पहुंच जायेंगे। इन 15 दिन में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जायेगा ... चाहे जो भी मुश्किल आये, हमारी सरकार वित्तीय अनुशासन बनाये रखने और आपको (किसानों को) बचाने के लिये प्रतिबद्ध है।” कुमारस्वामी ने कहा कि वह और उप मुख्यमंत्री जो परमेश्वर काईस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी भी किसानों की कर्ज माफी के लिये प्रतिबद्ध हैं। वहां मौजूद लोगों से उन्होंने कहा, “ मैं इसकी (कर्ज की रकम की) गणना कर रहा हूं। चाहे वह हजारों करोड़ रुपये की रकम क्यों नहीं हो ... आपको बचाना ही हमारी सरकार का जिम्मेदारी है। ” बैठक में परमेश्वर, विधानसभा में विपक्ष के उपनेता गोविंद काराजोला (भाजपा) और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि वह दो - तीन दिन में राष्ट्रीयस्तु बैंक में प्रतिक्रिया कीजेंगे की बैठक बुलायेंगे और उनकी ओर से किसानों को दिये जाने वाले कर्ज के बारे में सूचना मांगेंगे।

- पीटीआई

राजस्थान सहित 10 राज्यों पर बिजली उत्पादक कंपनियों का 32,024 करोड़ रुपये बकाया

नयी दिल्ली। बिजली उत्पादक कंपनियों को राज्य विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा बकाये के भुगतान के मामले में महाराष्ट्र, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा समेत 10 राज्यों की स्थिति खराब है। सरकारी पोर्टल प्राप्ति से यह जानकारी मिली है। अन्य चार राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और उत्तराखंड है।

मंगलाय न बिजली उत्पादकों और वितरक कंपनियों के बीच विद्युत खरीद में भुगतान की समस्या पर बिजली उपारदर्शिता लाने और विवाद को संभवना वृद्ध करने के इरादे से आज प्राति नान से एए और वैब पोर्टल लल शुरु किया। बिजली उत्पादकों के बिलों में बिजली उपारदर्शिता लाने के लिये बिजली खर्च में भुगतान की पुष्टि और विश्लेषण' (पेमेंट रैटिफिकेशन एनालिसिस इन पावर प्रोव्हरमेंट फॉर बिलिंग ट्रांस्परेसी इन इन्वायर्समिंट आफ जेनरेटर्स—प्राति) एए और वैब पोर्टल बिजली उत्पादक कंपनियों के

विभिन्न दीर्घकालीन बिजली खरीद समझौतों से संबंधित बचत (इनवायस) और भुगतान के आंकड़ों के को प्रदर्शित करवाया। इससे मासिक आधार पर एक पता चलेगा कि बिजली खरीद को लेकर वित्त-कंपनियों पर किटना बकाया है और उन्होंने किटना भुगतान किया है। पोटेल के अनुसार इस साल फरवरी तक इन राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों द्वारा उत्पादक कंपनियों को भुगतान में कम-से कम 2240 दिनों या उससे अधिक की देरी की है। बिजली मंत्री आर के सिंह द्वारा आज शुरू पोटेल के अनुसार बिजली उत्पादक कंपनियों पर फरवरी 2018 तक कुल 32,024 करोड़ रुपये बकाया है। एए और पोटेल जवाब देते हुए सिंह ने कहा कि बिजली उत्पादक कंपनियों खासकर स्वतंत्र बिजली उत्पादकों का बकाया चिंता का कारण है और इसका पहलू से इसमें पारदर्शिता आणी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भुगतान के बारे में आंकड़ा उत्पादक

कंपनियों से लेने के बजाए इस बारे में आंकड़ों उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वितरण कंपनियों की दी जानी चाहिए। इससे इस पहल की कक्षा बढ़ेगी। एक अधिकारी ने कहा कि पोर्टल और एप में से बतलाव अगले एक सप्ताह में किया जाएगा। उसमें कहा कि आंकड़ों वास्तविक समय पर आधारित नहीं हैं क्योंकि बिज (निवायस) आने के बाद भुगतान में 30 दिन का अंतराल होता है। इसमें फिलहाल 61 बिजली वितरण कंपनियों तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की 23 उत्पादक कंपनियों को शामिल किया गया है। फरवरी में सर्वाधिक 13,446 बिजली का बकाया स्वतंत्र बिजली उत्पादक का था। उसके बाद एनटीपीसी 8,454 तथा डीवीएस 2,275 करोड़ रुपये का स्थान है। एक अधिकारी ने कहा कि इसमें अभी भागीदारी स्वीचिंक है और कुछ उत्पादक कंपनियों ने पिछले छह महीने के बिजल और भुगतान के आंकड़े नहीं दिये हैं।

पृष्ठ एक से जारी...

काँफी...

तातानी लोग को गुमराह कर सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कह चुका है कि काँफ़ी से कैसर नहीं होता। अमेरिकी सरकार के गाइडलाइन में भी काँफ़ी व लाइफ़स्टाइल का हिस्सा सुझाया है। 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि कैसर के संभावित कारणों की सूची से हटाते हुए कहा था कि काँफ़ी पीने, ब्रेस्टफ़ीडिंग से रोकें और पैरेंटिंग के कैसर का काँफ़ी संभव नहीं आता। बल्कि लिबर और गर्भाशय कैसर जोखिम को कम करने की रिपोर्ट्स हैं। कमपनियां तो तर्क दे हैं कि एंज्रिलएमआईड को बंद नहीं किया जा सका क्योंकि फ़िल फ़्लेवर ख़त्म हो जायेगा - न्यूज डेस्क

उत्तर...

मई जुलाई से औसत की अवधि के लिये आज जलवायु दीर्घकालिक औसत पूर्वानुमान के तहत मौसम विलिहाज से देश के चार भौगोलिक क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत क्षेत्र में औसत बारिश का अनुमानित शत प्रतिशत रहने के अलावा दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र में इसका स्तर 95% और पूर्वी-चर क्षेत्र में 93% रहने अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने मासिक आधुनिक जुलाई में देश में औसत बारिश का स्तर सामान्य अनुमान का 101% और औसत बारिश में 94% रहने संभावना बताया है। विभाग के मानकों के मुताबिक देश में बारिश का सामान्य औसत स्तर 89 सेमी है। यह स्तर 1951 से 2000 के बीच हुई बारिश की औसत मात्रा के मुताबिक नियत किया गया है। - पीटीओ

प्रवर्तन...

अन्य लोगों को खिलाफ निदेशालय ने 2013 में मुंबई पुलिस को आर्थिक अपराध शाखा के साथ मिलकर नौ लॉन्गवूड कानून के तहत मामला दायर किया था। उल्लेखनीय है कि यह मामला 13,000 निवेशकों को धोखा देकर कुल 5,600 करोड़ रुपये के घोटाले का बुरा है। एजेंसी का आरोप है कि मामले में अभियुक्तों ने आपराधिक साजिश करते हुये निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की। जाली दस्तावेज बनाये, खातों हेरफेर किया व निवेशकों को एनएसईएल के प्लेटफॉर्म पर सौदे करने के लिये प्रेरित किया

- पीटीआई

23 करोड़...

पर अपनी कमाई को खर्च करने के कारण गरीबी में धकेल दिए जाते हैं और बहुत से लोग स्वास्थ्य सेवाओं को ही पाने में असमर्थ हैं। यह अस्वीकार्य है।” डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ने आगे बताया गया की देश की आबादी का 3.9 फीसदी या 5.1 करोड़ भारतीय अपने घरेलू बजट का एक चौथाई से ज्यादा खर्च इलाज पर ही कर देते हैं। जबकि श्रीलंका में ऐसी आबादी महज 0.1 फीसदी है, ब्रिटेन में 0.5 फीसदी, अमेरिका में 0.8 फीसदी और चीन में 4.8 फीसदी है। इलाज पर अपनी आय का 10 फीसदी से ज्यादा खर्च करने वाली आबादी का वैश्विक औसत 11.7 फीसदी है। इनमें 2.6 फीसदी लोग अपनी आय 25 फीसदी से ज्यादा हिस्सा इलाज पर खर्च करते हैं और दुनिया के करीब 1.4